



ORIGINAL RESEARCH PAPER

History

मेरठ मण्डल में महिला सशक्तिकरण में पंचायतों की भूमिका

KEY WORDS: पंचायती राज, संवैधानिक, जनप्रतिनिधि, रूढ़ीवादी।

निशा बालियान

शोधार्थी, इतिहास विभाग, एस० आर० टी० परिसर० है०न०ब०ग० विश्वविद्यालय श्रीनगर।

प्रो० जे०सी० जोशी

प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, एस० आर० टी० परिसर० है०न०ब०ग० विश्वविद्यालय श्रीनगर।

ABSTRACT

भारत में पंचायती राज की अवधारणा कोई नई बात नहीं है। भारत में पंचायती राज का पुराना इतिहास रहा है। समय और तत्कालीन परिस्थितियों ने उन आयामों का निर्धारण कर दिया। जिससे खुद ही पंचायतों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। 73वां संविधान संसोधन सम्पूर्ण देश में 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया है। इस संसोधन से अब पंचायतों को संवैधानिक स्वरूप प्राप्त हुआ है और महिलाओं की भागीदारी के लिए पंचायत के प्रत्येक स्तर पर कम से कम एक तिहाई पद आरक्षित किये गये हैं। मेरठ मण्डल में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण समाज विकास की ओर अग्रसर है और महिलाएँ इस व्यवस्था में एक सकारात्मक भूमिका निभाती हैं। महिला जनप्रतिनिधि समग्र समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाएँ अब रूढ़ीवादी सोच को छोड़कर काम करती हैं और अपने क्षेत्र का विकास करती हैं।

भारत में पंचायती राज की अवधारणा कोई नई बात नहीं है। भारत में पंचायती राज का पुराना इतिहास रहा है। समय और तत्कालीन परिस्थितियों ने उन आयामों का निर्धारण कर दिया। जिससे खुद ही पंचायतों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। भारत में विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप पंचायतें लगभग समाप्त हो गईं परन्तु फिर भी इन्होंने अपना अस्तित्व बनाए रखा। वर्तमान में पंचायतें राज व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बन गईं। हमारे देश में 1935 में महिलाओं को मतदान का हक मिल गया, इंडियन वीमेन्स कौंसिल का जन्म ऐनी बेसेन्ट की अध्यक्षता में हुआ, यह संगठन मुख्य रूप से शिक्षा राजनीति और कानूनी सुधारों का पक्षधर था।

1976 में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया पूरे विश्व में केवल 05 देशों में ही महिलाएँ संसद की 30 प्रतिशत सीटों पर आसीन हैं इसके अतिरिक्त 36 देशों में 05 प्रतिशत से भी कम संसदीय पद उनके पास हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा भेदभाव लिंग भेद है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है लेकिन वहाँ महिलाएँ स्वावलम्बी हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं बांग्लादेश में महिलाएँ प्रधानमंत्री रही हैं किन्तु यहाँ महिलाएँ आज भी परतन्त्र हैं। मेरठ मण्डल में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण समाज विकास की ओर अग्रसर है और महिलाएँ इस व्यवस्था में एक सकारात्मक भूमिका निभाती हैं, महिलाएँ ग्रामीण परिवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। महिलाओं की कुछ समस्याएँ ऐसी होती हैं, जिन पर पुरुषों का ध्यान ही नहीं जाता। अतः ये महिला जनप्रतिनिधि समग्र समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

73वां संविधान संसोधन सम्पूर्ण देश में 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया है। इस संसोधन से अब पंचायतों को संवैधानिक स्वरूप प्राप्त हुआ है और महिलाओं की भागीदारी के लिए पंचायत के प्रत्येक स्तर पर कम से कम एक तिहाई पद आरक्षित किये गये हैं। मेरठ मंडल के पांचों जिलों (मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर) में 1995 से 2015 के मध्य जो चुनाव हुए हुए हैं। उनके आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्ष 1995 के चुनाव पंचायतों के केवल एक तिहाई पदों पर ही महिलाओं का निर्वाचन हुआ परन्तु समय के साथ-साथ परिस्थितियाँ बदल रही हैं और धीरे-धीरे महिलाओं की भागीदारी पंचायतों में बढ़ रही है जिसके कारण लगभग आधे पदों पर निर्वाचित होकर आती हैं और कभी-कभी वह पंचायत के किसी स्तर के निर्वाचन में कुल निर्वाचन 60 प्रतिशत पदों पर निर्वाचित होती हैं। यद्यपि अभी भी वे अपने अधिकारों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक नहीं हैं। मेरठ मंडल में राजनीति में अपरधोकरण भी आजकल आम बात है ऐसी परिस्थितियों में एक महिला खुलकर अपनी बात नहीं कह पाती और कई बार वह स्वतन्त्र निर्णय भी नहीं ले पाती। कुछ महिलाएँ निर्वाचित तो हो जाती हैं परन्तु उन्हें अपने पद और अधिकारों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता सब कुछ उसके पुरुष अभिभावक ही देखते हैं, अतः अभी भी 73वें संविधान संसोधन की मंषाएँ पूर्ण नहीं हुई हैं। आज भी एक महिला जनप्रतिनिधि और विशेष तौर पर दलित महिला जनप्रतिनिधि कोई भी निर्णय स्वतंत्र रूप से तो छोड़िये, वह कोई भी निर्णय नहीं लेती, और कभी-कभी तो उसे लोगों की समस्याओं और समाधानों का पता ही नहीं होता यह सब इसीलिए क्योंकि हमारे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को आज भी हीन दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें इस लायक समझा ही नहीं जाता की वह कोई भी स्वतंत्र निर्णय ले सके लेकिन जिस तरह हर रात के पीछे एक सवेरा आता है उसी तरह आज महिलाएँ अपने हक के लिए लड़ रही हैं और वह दिन दूर नहीं है जब वह खुद अपने लिए और अपने पद के अनुरूप स्वतंत्र निर्णय ले सके।

मेरठ मंडल में वर्ष 2005 में जिला पंचायत स्तर पर कुल 126 पदों में से 61 पदों पर

स्रोत— जिला पंचायत कार्यालय।

महिला जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ जोकि कुल निर्वाचन का 48.41 प्रतिशत है और वर्ष 2015 में कुल 135 पदों में से 49 पदों पर महिला जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ जो कि कुल निर्वाचन का 36.30 प्रतिशत है इस प्रकार आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि महिला जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन प्रतिशत में कमी आई है। इसी प्रकार ब्लाक स्तर पर वर्ष 2005 में 3586 पदों में से 1407 पदों पर महिलाओं का निर्वाचन हुआ है जो कि कुल निर्वाचन का 39.24 प्रतिशत है और वर्ष 2015 में 3260 पदों में से 1333 पदों पर महिलाओं का निर्वाचन हुआ जोकि कुल निर्वाचन का 40.89 प्रतिशत जोकि 2005 की तुलना में ज्यादा है। मेरठ मंडल के ग्राम पंचायत स्तर पर वर्ष 2005 में 2224 पदों में से 1079 पदों पर महिलाओं का निर्वाचन हुआ जोकि कुल निर्वाचन का 48.52 प्रतिशत है और वर्ष 2015 में 2119 पदों में से 832 पदों पर महिला जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ जोकि कुल निर्वाचन का 39.29 प्रतिशत है जोकि 2005 की तुलना में कम है। इस प्रकार उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि महिलाओं का निर्वाचन स्तर में 2015 में 2005 की अपेक्षा कमी आयी है।

जनपद	पंचायत स्तर	2005			2015		
		महिला	पुरुष	कुल	महिला	पुरुष	कुल
मेरठ	जिला स्तर	12	19	31	14	20	34
	ब्लाक स्तर	337	465	802	346	518	864
	ग्राम स्तर	237	223	460	198	400	598

बुलंदशहर	जिला स्तर	25	21	46	14	29	53
	ब्लाक स्तर	462	744	1206	548	774	1322
	ग्राम स्तर	420	459	879	391	566	957
बागपत	जिला स्तर	9	10	19	08	13	21
	ब्लाक स्तर	197	287	484	211	309	520
	ग्राम स्तर	122	115	237	107	138	245
गजियाबाद	जिला स्तर	7	9	16	7	11	18
	ब्लाक स्तर	260	445	705	138	204	342
	ग्राम स्तर	181	224	405	68	98	166
गौतमबुद्ध नगर	जिला स्तर	8	6	14	6	3	9
	ब्लाक स्तर	151	238	389	90	122	212
	ग्राम स्तर	119	124	243	68	85	153

स्रोत— जिला पंचायत कार्यालय।

महिला जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ जोकि कुल निर्वाचन का 48.41 प्रतिशत है और वर्ष 2015 में कुल 135 पदों में से 49 पदों पर महिला जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ जो कि कुल निर्वाचन का 36.30 प्रतिशत है इस प्रकार आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि महिला जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन प्रतिशत में कमी आई है। इसी प्रकार ब्लाक स्तर पर वर्ष 2005 में 3586 पदों में से 1407 पदों पर महिलाओं का निर्वाचन हुआ है जो कि कुल निर्वाचन का 39.24 प्रतिशत है और वर्ष 2015 में 3260 पदों में से 1333 पदों पर महिलाओं का निर्वाचन हुआ जोकि कुल निर्वाचन का 40.89 प्रतिशत जोकि 2005 की तुलना में ज्यादा है। मेरठ मंडल के ग्राम पंचायत स्तर पर वर्ष 2005 में 2224 पदों में से 1079 पदों पर महिलाओं का निर्वाचन हुआ जोकि कुल निर्वाचन का 48.52 प्रतिशत है और वर्ष 2015 में 2119 पदों में से 832 पदों पर महिला जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ जोकि कुल निर्वाचन का 39.29 प्रतिशत है जोकि 2005 की तुलना में कम है। इस प्रकार उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि महिलाओं का निर्वाचन स्तर में 2015 में 2005 की अपेक्षा कमी आयी है।

सन्दर्भ सूची

1. झा द्विजेन्द्र नारायण एवं श्रीमति कृष्ण मोहन, प्राचीन भारत का इतिहास, 2003, पृ०सं०-128
2. मेरठ मंडल में महिला जनप्रतिनिधियों के साक्षात्कार से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित।
3. सैनी डॉ० अभिलाषा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण दशा एवं दिशा।
4. शर्मा डॉ० नीरजा, महिला सशक्तिकरण, 2013, पृ०सं०-99
5. माथुर डा० सावित्री, जैन डा० मोनिका, आधुनिक समाज में महिलाएँ समस्याएँ एवं समाधान, पृ०सं०-206
6. शर्मा, डॉ० नीरजा, महिला सशक्तिकरण, 2013, पृ०सं०-236
7. गर्ग, प्रियंका, महिला विवाह देहेज एवं दाम्पत्य समस्याएँ, पृ०सं०-236
8. शर्मा, डॉ० नीरजा, महिला सशक्तिकरण, 2013, पृ०सं०-97
9. श्रीवास्तव डॉ० मधुलिका, महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम सशक्तिकरण महिलाओं की बदलती प्रस्थितियाँ।